अभ्यास प्रश्न
व्याख्यात्मक हल सहित

व्याख्यात्मक प्रश्न

1. कैबिनेट मिशन के सन्दर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं ?

   1. इसने एक संघीय सरकार
   2. इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया।
   3. इसने आईसीएस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबन्ध किया।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

   (a) केवल 1
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) कोई नहीं

2. भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया ?

   (a) न्यायपालिका एवं विधायिका (लेजिस्लेचर) के बीच शक्ति का पृथक्करण
   (b) केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों की अधिकारिता
   (c) भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वाइसरॉय की शक्तियाँ
   (d) उपर्युक्त में से कोई नही

3. 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित मे से कौनसी प्रमुख विशेषता/विशेषताएं है/हैं ?

   1. प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध-शासन की व्यवस्था
   2. मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था
   3. केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण

   निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए-

   (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियो का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है।

   (a) मॉर्ले मिंटो सुधार, 1909
   (b) मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919
   (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
   (d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

5. भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उददेश्य था-

   (a) जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपिय लोगों को बराबरी पर रोकना
   (b) देशी प्रेस की स्वतंत्रतापर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था
   (c) प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके
   (d) शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना

6. 1946 मे निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापित थे-

   (a) जवाहर लाल नेहरू
   (b) डॉ. एस. राधाकृष्णन
   (c) सी. राजगोपालाचारी
   (d) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

7. **कथन (A):** वेवेल योजना के अनुसार, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी।

   कारण (R): वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बन जाता।

   (a) कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है।
   (b) कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
   (c) कथन सही है, पर कारण गलत है।
   (d) कथन गलत है, पर कारण सही ह।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

   1. तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार-विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पारित होने के रूप में हुई।
   2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित आल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया।

   उपर्युक्त कथनों मे से कौनसा/से सही है/हैं ?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 और न ही 2

9. भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था ?

   (a) स्वराज पार्टी ने 1934 में
   (b) कांग्रेस पार्टी ने 1936 में
   (c) मुस्लिम लीग ने 1942 में
   (d) सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में

10. निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है ?

1. वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नही थी
2. वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी
3. वह बहुदलीय निकाय थी
4. उसने अनेक समितियों के माध्मय से कार्य किया

नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए-

कूटः

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 4 (d) 1,2, 3 और 4

11. भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को-

(a) ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया
(b) गवर्नर-जनरल द्वारा नामित किया गया
(c) विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया
(d) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया

12. भारतीय इतिहास के संदर्भ में, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य-

(a) उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे
(b) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे
(c) प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे
(d) सरकार द्वारा, संवैधानिक मामलों मे उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे।

13. निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था ?

(a) बी.आर. अंबेडकर
(b) जे.बी. कृपलानी
(c) जवाहर लाला नेहरू
(d) अल्लादी कृष्णास्वामी अय्ययर

14. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था ?

(a) डॉ. भीम राव अम्बेडकर
(b) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(c) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
(d) सी. राजगोपालाचारी

15. बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था-

(a) पश्चिम बंगाल से
(b) बंबई प्रेसीडेंसी से
(c) तत्कालीन मध्य भारत से
(d) पंजाब से

16. भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है ?

(a) संविधान की उद्देशिका में
(b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में
(c) मूल कर्त्तव्यों में
(d) नवीं अनुसूची में

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत के संविधान में 20 भाग हैं।
2. भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं।
3. भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1,2 और 3

18. 'भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।' यह उपबन्ध किसमें किया गया है ?

(a) संविधान की उद्देशिका
(b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(c) मूल अधिकार
(d) मूल कर्त्तव्य

19. भारत के संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है ?

(a) उद्देशिका
(b) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(c) मूल अधिकार
(d) सातवीं अनुसूची

20. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये तत्त्व देश के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं।
2. इन तत्त्वों में अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (एन्फोर्सिएबल) नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

21. भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा, देश के शासन के लिए आधारभूत है ?

(a) मूल अधिकार
(b) मूल कर्त्तव्य
(c) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व
(d) मूल अधिकार तथा मूल कर्त्तव्य

22. भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें-

1. भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता।
2. ग्राम पंचायतों का संगठन
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
4. सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना।

उपरोक्त में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिम्बित होता है/होते है-

(a) 1, 2 और 4 (b) 2 और 3
(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6-14 वर्षों के आयु-वर्ग के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया।
2. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है।
3. शिक्षा, भारत के संविधान के 42वें संशोधन, 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है ?

(a) 1, 2 तथा 3
(b) केवल 1 तथा 2
(c) केवल 2 एवं 3
(d) केवल 1 तथा 3

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है।
2. संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किन्तु यह मूल अधिकार नहीं है।
3. भारत के संविधान में अनुच्छेद 300A उस समय केन्द्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

25. भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन-से अनुच्छेद में उपबन्ध है कि चौदह वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा ?

(a) अनुच्छेद 24
(b) अनुच्छेद 45
(c) अनुच्छेद 330
(d) अनुच्छेद 368

26. सूची-I (भारत के संविधान के अनुच्छेद) को सूची-II (उपबन्ध) के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I	सूची-II
A. अनुच्छेद 14	1. राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा
B. अनुच्छेद 15	2. राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा
C. अनुच्छेद 16	3. 'अस्पृश्यता' का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है
D. अनुच्छेद 17	4. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	4	1	3
(b)	3	1	4	2
(c)	2	1	4	3
(d)	3	4	1	2

27. भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह हैं

(a) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20
(b) अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19
(c) अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18
(d) अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17

28. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है

(a) राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना
(b) सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना
(c) गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना
(d) सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना

29. राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है ?

(a) 51 (b) 48 क
(c) 43 क (d) 41

30. निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है ?

(a) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
(b) संपत्ति का अधिकार
(c) समानता का अधिकार
(d) संवैधानिक उपचार का अधिकार

31. सूची-I (भारतीय संविधान का अनुच्छेद) को सूची II (प्रावधान) से सुमेल कीजिए-

सूची-I	सूची-II
A. अनुच्छेद 16 (2)	1. किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
B. अनुच्छेद 29 (2)	2. किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
C. अनुच्छेद 30 (1)	3. सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।
D. अनुच्छेद 31 (1)	4. किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा सम्पोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	4	3	1
(b)	3	1	2	4
(c)	2	1	3	4
(d)	3	4	2	1

32. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है ?

(a) गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ
(b) दीव रूम्भात की खाड़ी में एक टापू है
(c) दमन और दीव को भारत के संविधन के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया
(d) दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है।
2. किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नामनिर्देशित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है।
2. प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

35. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
2. भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

36. निम्नलिखित में से कौन-सा/से मंत्रिमंडल सचिवालय का/के कार्य है/हैं ?

1. मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना।
2. मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता।
3. मंत्रलयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2 और 3

37. निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं ?

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना।
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना।
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को, भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।

4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 2

38. भारत के संदर्भ में, संसदीय शासन-प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सिद्धान्त संस्थागत रूप में निहित है/हैं ?

1. मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं।
2. जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं।
3. राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

39. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. केंद्र में मंत्रिपरिषद् संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
2. संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
3. विधि-निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

40. भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वे संसद के समक्ष निम्न में से किसे रखें ?

1. केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को
2. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को
3. CAG के प्रतिवेदन को
4. अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को

निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) 2 और 4

(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जवाहर लाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे।
2. जवाहर लाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया।
3. भारत के प्रथम गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

(a) 1 और 2 (b) केवल 3

(c) केवल 1 (d) 1 और 3

42. भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि-

(a) लोक सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है।

(b) संसद संविधान का संशोधन कर सकती है

(c) राज्य सभा को भंग नहीं किया जा सकता

(d) मंत्रिपरिषद, लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है

43. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राज्य सभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है।
2. राज्य सभा अनुदानों की माँगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
3. राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

44. जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट (रेफर) किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है ?

(a) उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत

(b) उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का तीन-चौथाई बहुमत

(c) सदनों का दो-तिहाई बहुमत

(d) सदनों का पूर्ण बहुमत

45. संघ की सरकार (यूनियन गवर्नमेंट) के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:.

1. राजस्व विभाग, संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले केन्द्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
2. भारत की संसद के प्राधिकरण (ऑथराइजेशन) के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता।
3. लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों (डिंसबर्समेंट्स) के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

46. भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेखन नहीं है।
2. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही पुन:स्थापित किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

47. निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है ?
(a) लोक लेखा समिति
(b) प्राक्कलन समिति
(c) सरकारी उपक्रम समिति
(d) याचिका समिति

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते।
2. जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

49. यदि राज्य सभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तो तत्पश्चात् क्या होगा ?
(a) लोक सभा, राज्य सभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है।
(b) लोक सभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती
(c) लोक सभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य सभा को लौटा सकती है
(d) राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोक सभा में एक विधेयक की पुन:स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है।
2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की माँग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

51. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

भारत का महान्यायवादी
1. लोक सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है
2. लोक सभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है
3. लोक सभा में बोल सकता है
4. लोक सभा में मतदान कर सकता है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(a) केवल 1
(b) 2 और 4
(c) 1, 2 और 3
(d) केवल 1 और 3

52. भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है-
(a) सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति माँगना
(b) विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से सूचनाएँ एकत्र करने देना
(c) अनुदान मांगों में किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना।
(d) कुछ सदस्यों के असंगत अथवा हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना

53. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्य सभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता।
2. चुनावी विवादों में वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है।
3. भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर बनी है।

उपरोक्त में से कौन सही है ?
(a) केवल 1
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) कोई नहीं

54. लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालता/ती है।
2. चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं, किन्तु चुनाव की तिथि से छह महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ता है।
3. अगर वह त्याग पत्र देना चाहता/चाहती है तो उसका त्यागपत्र उप-लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित होगा।

उपरोक्त में से कौन सही है ?
(a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1, 2 और 3
(d) कोई नहीं

55. भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन-सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ?
(a) राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन तथा राज्य के नाम में परिवर्तन
(b) इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई हो।
(c) राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना तथा राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेन्शन निर्धारित करना।
(d) चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण तथा चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण

56. सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन-से तरीके प्रचलित हैं ?

1. संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना।
2. विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही कन्सोलिडेटेड फंड से राशि की निकासी करना।
3. पूरक अनुदानों तथा लेखामत संबंधी प्रावधान
4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा बृहद अर्थशास्त्रीय पूर्व सूचना तथा व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम का सावधिक अथवा कम से कम वर्ष मध्य समीक्षा
5. संसद में वित्त विधेयक की प्रस्तुति

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें-

(a) 1, 2, 3 और 5 (b) 1, 2 और 4
(c) 3, 4 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

57. लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है-

1. साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान
2. वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान
3. संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

58. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किया जाता है।
2. लोक लेखा समिति में लोक सभा सदस्य, राज्य सभा सदस्य और उद्योग और व्यापार के कुछ जाने-माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

59. **कथन (A) :** भारत संघ में मंत्रि परिषद् संयुक्त रूप से लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के प्रति उत्तरदायी है।

कारण (R) : लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं।

कूट:

(a) A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(b) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) A सही है, परन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, परन्तु R सही है।

60. प्रथम लोक सभा के अध्यक्ष कौन थे ?

(a) हुक्म सिंह
(b) जी. वी. मावलंकर
(c) के. एम. मुंशी
(d) यू. एन. ढेबर

61. निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. केवल राज्य सभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है।
2. आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोक सभा द्वारा पारित किए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 तथा 2 (d) कोई नहीं

62. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोकसभा अध्यक्ष में यह शक्ति निहित है कि वह सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित कर दे परन्तु सत्तावसान होने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन को आहूत कर सकते हैं।
2. यद्यपि लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक आदेश न भी हो तब भी, ऐसी स्थिति छोड़कर जब लोकसभा समय से पहले भंग कर दी गयी हो या उसकी अवधि बढ़ा दी गई हो, पाँच वर्ष की अवधि खत्म हो जाने पर लोकसभा स्वत: भंग हो जाती है।
3. लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात भी 'सदन की अगली बैठक से एकदम ठीक पहले' तक लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद पर आसीन रहते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

63. भारत के लोक वित्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत के लोक लेखा से संवितरण संसद के मत के अधीन है।
2. भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिक निधि का उपबन्ध है।
3. रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

64. भारतीय संसद् के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है ?

(a) विनियोजन विधेयक का, कानून बनने से पूर्व, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है

(b) विनियोजन अधिनियम के अधीन विनियोजन हुए बिना भारत के संचित निधि में से धन नहीं निकाला जा सकता

(c) नए कर प्रस्तावित करने के लिए वित्त विधेयक का होना आवश्यक है जबकि चालू करों की दर में बदलाव के लिए किसी अन्य विधेयक/अधिनियम की आवश्यकता नहीं है।

(d) राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई धन-विधेयक नहीं लाया जा सकता।

65. निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे ?

(a) के.वी.के. सुन्दरम
(b) जी. एस. ढिल्लों
(c) बलिराम भगत
(d) हुकुम सिंह

66. निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है।
2. लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी।
3. भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग (निरसन) बिल को पारित करने के लिए हुई थी।

इन कथनों में से कौन से सही हैं ?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

67. निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है-

(a) साधारण विधेयक
(b) धन विधेयक
(c) वित्त विधेयक
(d) संविधान संशोधन विधेयक

68. निम्न कथनों में से कौन-सा एक सही है ?

(a) केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं

(b) राज्यसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है

(c) किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री के पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है

(d) मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है।

69. निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोक-लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं।
2. संसदीय कार्य मंत्रलय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है।
3. विभिन्न मंत्रलयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद-सदस्यों को नामित करते हैं।

इनमें से कौन-सा कथन सही हैं ?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1,2 और 3

70. निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

वित्त आयोग का/के कार्य है/हैं-

1. भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना।
2. प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बाँटना।
3. सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार।
4. संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना।

इन कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) 2 और 3
(c) 3 और 4 (d) 1,2 और 4

71. भारतीय राजनीति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

(a) योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है

(b) राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

(c) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की न्यूनतम निर्धारित आयु 40 वर्ष है।

(d) राष्ट्रीय विकास परिषद् में केन्द्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्य मंत्री होते हैं।

72. लोकसभा का कार्यकाल-

(a) किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता
(b) एक बार में छः महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
(c) आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है
(d) आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।

73. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है ?

(a) धन विधेयक संसद में दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है

(b) लोक सभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं

(c) लोक सभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अन्दर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है

(d) राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोक सभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता

74. अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है–

(a) मर्यादा (b) पक्षत्याग
(c) अंतर्प्रश्न (d) बैठ जाना

75. एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैद्यता अन्य शर्तों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि–

(a) वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले

(b) वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो

(c) उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो

(d) वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करें

76. केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है ?

(a) परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत

(b) अपीली अधिकारिता के अंतर्गत

(c) मूल अधिकारिता के अंतर्गत

(d) रिट अधिकारिता के अंतर्गत

77. भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है ?

(a) भारत का राष्ट्रपति

(b) संसद

(c) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति

(d) विधि आयोग

78. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है ?

(a) भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता

(b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं

(c) भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है

(d) विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा, बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है।

79. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया गया ?

1. अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार
2. अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रें में प्रशासन का स्तर उन्नत बनाने के लिए अनुदान संबंधी प्रावधान
3. अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें–

(a) केवल 1 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

80. भारतीय कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों/विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है/हैं ?

1. उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए अधिकश्त है।
2. यदि कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर करता है उसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होता।
3. किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर के सही उत्तर का चयन करें।

(a) केवल 1 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

81. निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्रधिकार के अंतर्गत है ?

1. भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्यों के बीच कोई विवाद।
2. संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका के चुनाव से संबंधित कोई विवाद।
3. भारत सरकार तथा किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद।
4. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें–

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 4 (d) 3 और 4

82. सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्ता की रक्षा के लिए प्रावधान क्या है ?

1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे।
2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही पद से हटाए जा सकते हैं।
3. न्यायाधीशों का वेतन कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान की जरूरत नहीं होती है।
4. भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी नियुकितयां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ही की जाती है।

निम्नलिखित में से कौन सही है-

(a) 1 और 3 (b) 3 और 4
(c) केवल 4 (d) 1, 2, 3 और 4

83. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है।
2. उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवा-निवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्रातिधकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

84. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. न्यायाधीश (जांच) विधेयक 2006 के अंतर्गत एक न्यायिक परिषद् को स्थापित करने का विचार है जो, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेगी।
2. घेरलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) कोई नहीं

85. **कथन (A):** भारत में प्रत्येक राज्य के राज्यक्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है।

कारण (R): भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो।

कूट:

(a) A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(b) A और R दोनों सही हैं, परन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) A सही है, परन्तु R गलत है।
(d) A गलत है, परन्तु R सही है।

86. जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायामूर्ति कौन थे ?

(a) एम. हिदायतुल्लाह
(b) ए.एम. अहमदी
(c) ए.एस. आनन्द
(d) पी.एन भगवती

87. निम्न कथनों पर विचार कीजिए-

1. कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थाई न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता।
2. कोई व्यक्ति, भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 तथा 2 (d) कोई नहीं

88. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वहीं है जो संविधान ने प्रदान की है।
2. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2 (d) कोई नहीं

89. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

1. चल कोष्ठिकीय (मोबाइल सेल्युलर) कंपनियों के साथ विवाद
2. वाहन-दुर्घटना मामले
3. पेंनशन मामले

उपरोक्त में से किसके/किनके लिए लोक अदालतें होती हैं ?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

90. संविधान (98वां संशोधन) अधिनियम किससे सम्बद्ध है ?

(a) सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केन्द्र को अधिकार देना।
(b) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन
(c) जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रें का पुनः समायोजन
(d) राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन

91. भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

(a) अनुच्छेद 257
(b) अनुच्छेद 258
(c) अनुच्छेद 355
(d) अनुच्छेद 356

92. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जिला में उच्चतम दण्ड न्यायालय, जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है।
2. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा होती है।
3. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को सात वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए।
4. यदि सेशन न्यायाधीश मृत्यु दण्ड का निर्णय दे तब मृत्यु दण्ड देने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है।

कूट:

(a) 1 और 2
(b) 2, 3 और 4
(c) 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

93. गुजरात में विधानसभा के चुनाव (वर्ष 2002 में) को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अन्तर्गत किया ?

(a) अनुच्छेद 142
(b) अनुच्छेद 143
(c) अनुच्छेद 144
(d) अनुच्छेद 145

94. 'संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बाहय आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे'-ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है ?

(a) अनुच्छेद 215 (b) अनुच्छेद 275
(c) अनुच्छेद 325 (d) अनुच्छेद 355

95. भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है-

(a) अपनी पहल पर
(b) तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है
(c) तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो।
(d) तभी जब वह मामला देश की एकता व अखण्डता के लिए खतरा पैदा करता हो।

96. भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है ?

(a) संसदीय समितियों के माध्यम से
(b) विभिन्न मंत्रलयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से
(c) प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदना भिजवा कर
(d) कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर

97. भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. देश में 21 उच्च न्यायालय हैं
2. उनमें से तीन का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है।
3. किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है।
4. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं।

इनमें से कौन सा/कौन से वक्तव्य सही है/हैं ?

(a) 1, 2 और 4 (b) 2 और 3
(c) 1 और 4 (d) केवल 4

98. अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री-

(a) के लिए आवश्यक नहीं वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि से छह माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है।
(b) के लिए आवश्यक नहीं कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो ही, किंतु नियुक्ति की तिथि से छह माह के अंदर उसका लोकसभा सदस्य बनना अनिवार्य है।
(c) संसद के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो
(d) लोकसभा का सदस्य अवश्य हो

99. निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केन्द्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार, क्रमश: लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा ?

(a) 91वां (b) 93वां
(c) 95वां (d) 97वां

100. जब केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने (वर्ष 2002 में) चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापिस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे अपनी सहमति दी ?

(a) अनुच्छेद 121 (b) अनुच्छेद 122
(c) अनुच्छेद 123 (d) अनुच्छेद 124

उत्तरमाला

1. (d)	**2.** (a)	**3.** (c)	**4.** (c)	**5.** (a)	**6.** (a)	**7.** (c)	**8.** (c)	**9.** (a)	**10.** (a)
11. (c)	**12.** (c)	**13.** (c)	**14.** (a)	**15.** (b)	**16.** (b)	**17.** (c)	**18.** (d)	**19.** (b)	**20.** (c)
21. (c)	**22.** (b)	**23.** (c)	**24.** (a)	**25.** (a)	**26.** (c)	**27.** (c)	**28.** (d)	**29.** (a)	**30.** (d)
31. (a)	**32.** (d)	**33.** (d)	**34.** (d)	**35.** (a)	**36.** (b)	**37.** (c)	**38.** (d)	**39.** (d)	**40.** (b)
41. (a)	**42.** (d)	**43.** (b)	**44.** (a)	**45.** (d)	**46.** (c)	**47.** (b)	**48.** (b)	**49.** (a)	**50.** (d)
51. (c)	**52.** (a)	**53.** (d)	**54.** (b)	**55.** (b)	**56.** (a)	**57.** (a)	**58.** (a)	**59.** (d)	**60.** (b)
61. (a)	**62.** (d)	**63.** (b)	**64.** (c)	**65.** (a)	**66.** (d)	**67.** (d)	**68.** (c)	**69.** (d)	**70.** (b)
71. (b)	**72.** (c)	**73.** (a)	**74.** (d)	**75.** (c)	**76.** (c)	**77.** (b)	**78.** (c)	**79.** (a)	**80.** (c)
81. (c)	**82.** (a)	**83.** (a)	**84.** (b)	**85.** (d)	**86.** (d)	**87.** (a)	**88.** (d)	**89.** (d)	**90.** (b)
91. (a)	**92.** (d)	**93.** (b)	**94.** (d)	**95.** (b)	**96.** (a)	**97.** (d)	**98.** (a)	**99.** (a)	**100.** (c)

व्याख्यात्मक हल

1. (d) केबिनेट मिशन भारत में संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग हेतु जुलाई 1946 में आया था। अत: प्रश्नगत दिये गये सभी विकल्प असत्य है।

2. (a) भारत सरकार अधिनियम 1919 में न्यायपालिका एवं विधायिका (लेजिसलेचर) बीच की शक्ति को पृथक किया जिस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गर्वनर मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड ने निभाई।

3. (c) भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उददेश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणियों में बांटा गया-(अ) आरक्षित (ब) हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांरित विषयों के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतोंको विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया।

जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिक्खों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया।

4. (c) ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एकीकृत भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों से मिलकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था तथापि रियासतों की अनिच्छा के कारण इस संघ का निर्माण नहीं किया जा सका।

5. (a) 1883 में लार्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया, इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों क मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे। इस प्रकार इस विधेकय का उददेश्य अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था।

6. (a) 24 अगस्त, 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर, 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहर लाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापित बनाया गया।

7. (c) अक्टूबर, 1943 ई. में लार्ड लिनलिथगो के स्थान पर बिस्काउंट वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई, 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार सेविस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून, 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवल योजना के प्रस्तावों मे कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगा, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवेल योजना का उददेश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांविधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उददेश्य कहीं से भी हिंदू-मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अत: कथन सत्य है, पर कारण गलत है।

8. (c) नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप मे पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित आल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था।

9. (a) मई, 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था।

10. (a) संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अत: संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह निर्वाचन प्रारंभिक (राज्य विधान मंडलों का) स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए समितियों का गठन किया था।

11. (c) विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर विधान सभाओं का निर्वाचन किया। इन विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा पुन: संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचन हुआ। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए थे।

12. (c) कैबिनट प्रतिनिधिमंडल (1946) द्वारा सिफारिश की गई योजना के अनुसार प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था।

13. (c) संविधान सभा ने 'संघ संविधान समिति' सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पं. जवाहर लाल नेहरू थे। मुख्य समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं-

1. नियम समिति — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2. संचालन समिति — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
3. रियासत समिति — डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
(देशी रियासतों से वार्ता के लिए)
4. प्रारूप समिति — डॉ. भीम राव अंबेडकर
5. सलाहकार समिति — सरदार वल्लभ भाई पटेल
इस समिति की दो उपसमितियां थीं-
(क) मूल अधिकार उपसमिति — जे.बी. कृपलानी
(ख) अल्पसंख्यक उपसमिति — एच.सी. मुखर्जी
6. संघ शक्ति समिति — जवाहरलाल नेहरू
7. संघ संविधान समिति — जवाहरलाल नेहरू
8. प्रांतीय संविधान समिति — सरदार वल्लभभाई पटेल

15. (b) 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉ. भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डा. अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसीडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम-आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। चूंकि विकल्प (a) में पश्चिम बंगाल है इसलिए यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉ. अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमत: निर्वाचित हुए थे। स्पष्ट है कि अभीष्ट विकल्प (b) है।

17. (c) भारत के संविधान में 24 भाग हैं और अनुच्छेदों की संख्या कुल मिलाकर 444 है।

18. (d) प्रश्न में उल्लिखित उक्ति 'भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें' भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 (क) मूल कर्त्तव्यों से उद्‌धत है।

19. (b) भारत के संविधान में 'कल्याणकारी राज्य' का आदर्श भाग चार के अनुच्छेद-36 से 51 तक में किया गया है, जिसे संविधान निर्माताओं द्वारा 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था।

20. (c) राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते है एवं ये तत्त्व संवैधानिक निदेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्यों के लिए सिफारिशें मात्र ही है। अत: इन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा राज्यों पर एनफोर्स नहीं किया जा सकता एवं ये प्रर्वतनीय नहीं है।

21. (c) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 से राज्य के नीति निदेशक तत्त्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं एवं विधि बनाने में इन तत्त्वों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।

23. (c) केवल 2 और 3

6-14 वर्ष के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया।

24. (a) अनुच्छेद 301-व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता । 44वाँ संशोधन मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1978 में लाया गया

27. (c) अनु. 13 में मौलिक अधिकारों से असंगतता रखने वाले विधियों की चर्चा है। अनु. 19-स्वतंत्रता का अधिकार। अनु. 20 भी स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में ही चर्चा करता है। अत: केवल अनु. 14, 15, 16, 17 और 18 में ही समता के अधिकार की चर्चा की गई है।

28. (d) मौलिक अधिकार जहाँ राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। इसमें सामाजिक और गांधीवादी दर्शन/विचारों के साथ-साथ आर्थिक आशय का समर्थन करने वाले सिद्धांत भी मौजूद हैं।

29. (a) अनु. 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। अनु. 48 A में वन, वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी बातें हैं। अनु. 43 A प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की चर्चा करता है। अनु. 41 में काम और शिक्षा का अधिकार आदि वर्णित है।

30. (d) डॉ. बी. आर. अंबेडकर के अनुसार 'यह संविधान की आत्मा और जान है।'

32. (d) दादरा और नगर हवेली वर्ष 1961 तक पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत थे न कि फ्रांसीसी।

33. (d) विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इसी उद्देश्य से इसकी संख्या 60 से 500 के मध्य निश्चित की गयी है, जो कि पूर्णत: स्पष्ट करता है कि राज्य की जनसंख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या से परस्पर संबंधित है तथा राज्य के राज्यपाल द्वारा यह अधिकृत है कि वह विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित कर सकें।

34. (d) भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है एवं सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। अत: विकल्प (d) उपर्युक्त उत्तर सही है।

35. (a) भारत के संविधान में मूलभूत रूप से यह सिद्धान्त है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद होते हैं व जब तक मंत्रिपरिषद् को लोकसभा का विश्वास रहता है, वे अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होगा।

36. (b) भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(2) से मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त कार्य करते हैं। अनुच्छेद 78 से विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, लेकिन केन्द्र में मंत्रिपरिषद् संसद के प्रति नहीं लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

38. (d) जवाहर लाल नेहरू की प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1947–52, 52–57, 57–62, 62–64 संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व किया। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे।

41. (a) अनु. 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। अनु. 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनु. 155 में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनु. 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं की संरचना की चर्चा है।

42. (d) भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

43. (b) धन विधेयक को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाती है, तथा अनुदानों की मांग पर मतदान का अधिकार भी लोकसभा में ही निहित होता है, अत: विकल्प (b) ही उचित है।

44. (a) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में निर्दिष्ट विधेयक उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा ही पारित किया जाता है।

45. (d) संघ की सरकार से संबधित सभी कथन जिनका उल्लेख प्रश्नकाल में किया गया है, उपर्युक्त एवं सही है। अत: विकल्प (d) सही है।

46. (c) भारतीय संविधान में न तो विश्वास मत प्रस्ताव और न अविश्वास मत प्रस्ताव का कोई उल्लेख है। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 118 में लोक सभा और राज्य सभा को अपने-अपने कार्य संचालन नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के कार्य संचालन नियम 198 के तहत कोई भी सदस्य स्पीकर को लिखित नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। स्पीकर इस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाते हैं तथा प्रस्ताव की स्वीकार्यता पक्ष या विपक्ष में अपना मत देने को कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 50 या इससे अधिक के पक्ष में होने पर इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाता है।

47. (b) लोक लेखा समिति 22 सदस्य (लोक सभा-15, राज्यसभा-7)

प्राक्कलन समिति. 30 सदस्य (केवल लोकसभा)

लोक उपक्रम समिति. 22 सदस्य (लोक सभा-15, राज्यसभा-7)

याचना समिति-15 सदस्य

48. (b) राज्य सभा का सभापति, उपराष्ट्रपति ही होता है, वह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता, जबकि उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जिसमें दिल्ली एवं पुदुचेरी सम्मिलित हैं, भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित करते हैं।

49. (a) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि राज्य सभा धन विधेयक में कोई अनुशंसा करती है, तो उसे लोक सभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। धन विधेयकों के संबंध में लोकसभा को आत्यन्तिक शक्ति है।

50. (d) भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार-

1. संविधान के संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. यदि वह संशोधन संघीय चरित्र का है, तो संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्यों का बहुमत एवं कम-से-कम 50 प्रतिशत राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है।

58. (a) लोक लेखा समिति में सिर्फ लोक सभा एवं राज्यसभा से संबंधित सदस्य ही शामिल होते हैं।

59. (d) भारत संघ के मंत्रिपरिषद् सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

60. (b) 1952 में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने

61. (a) केवल 1

62. (d) लोकसभा को आहुत किया जाना संसद के नए सत्र का आरंभ होता है। तत्संबंधी शक्ति केवल राष्ट्रपति को प्रदान की गई है (अनु. 85)। लोकसभा को दो प्रकार से भंग किया जा सकता है: (a) काल व्यतिक्रम द्वारा अर्थात इसके 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति पर (b) आपात काल में इसके कार्यकाल में की गई वृद्धि की समाप्ति पर (c) नई लोकसभा के गठन तक लोकसभाध्यक्ष पद पर बना रहता है।

63. (b) न्यायाधीशों के वेतन सरीखे नियत खर्चों के अतिरिक्त भारत की संचित निधि से किए जाने वाले तमाम व्यय संसद के मत के अधीन हैं। लेकिन भारत के लोक लेखा से व्यय हेतु ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अनु. 266 और 267 में क्रमश: संचित निधि, लोक लेखा तथा आकस्मित निधि की व्यवस्था है।

64. (c) किसी भी नए कर प्रस्ताव के लिए वित्त विधेयक की आवश्यकता होती है। जबकि वित्त विधेयक में सुझाए गए किसी भी परिवर्तन के लिए नए सिरे से संसद का मत लेना आवश्यक हो जाता है।

65. (a) हुकुम सिंह - 1962-1967, जी-एस. ढिल्लों - 1969-1975, बलिराम भगत - 1976-1977

66. (d) 1. अनु. 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तब i) जबकि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो ii) अंतत: दोनों सदनों में विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर मतैक्य नहीं बन पाता है iii) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त किए हुए 6 महीने गुजर चुके हैं और उसने विधेयक पारित भी नहीं किया है। 2. लोकसभा व राज्य सभा की पहली संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में 'दहेज निषेध विधेयक' को पारित करने हेतु बुलाई गई थी। 3. दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक 1967 में 'बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक' को पारित करने के लिए संपन्न हुई थी।

67. (d) संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।

68. (c) (a) राज्य सभा में 12 लोकसभा में 2 आंग्ल-भारतीय सदस्य मनोनीत होते हैं। (b) आंग्ल-भारतीय सदस्यों का मनोनयन केवल लोकसभा के लिए होता है। राज्य सभा में केवल कला, विज्ञान, साहित्य तथा सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रें में उल्लेखनीय कार्य कर चुके लोगों का मनोनयन होता है। (c) संविधानानुसार व्यक्ति-विशेष संसद का सदस्य बने बगैर भी मंत्री बन सकता है। उसे 6 महीनों के भीतर विधायिका की सदस्यता प्राप्त कर लेनी होगी। (d) अनु. 52 के अनुसार केवल राज्य व संघीय विधायिका के निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं।

70. (b) संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है जो प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद इस आयोग का गठन करते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के कार्य संविधान के अनुसार इस प्रकार हैं—(1) केन्द्र एवं राज्य के मध्य करों के शुद्ध आगामों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगामों के भाग के आवंटन के बारे में सिफारिश करना। (2) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करना। (3) सुदृढ़ वित्तीय हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करना।

71. (b) (a) योजना आयोग, योजना निर्माण में कार्यपालिका को सहायता प्रदान करने के लिए, कार्यपालिका के निर्णय द्वारा गठित एक सलाहकारी निकाय है। दूसरी तरफ, 'कार्यपालिका' संसद के स्थान पर विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। (b) अनु. 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि यदि संसद के दोनों सदन सत्रधीन नहीं है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। (c) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए किसी न्यूनतम आयु सीमा का उल्लेख नहीं है। (d) राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रीपरिषद के सदस्य राज्यों के सभी मुख्यमंत्री गण तथा योजना आयोग के तमाम सदस्य शामिल हैं।

72. (c) अनु. 83 में कहा गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष की समयावधि तक बढ़ाया जा सकेगा।

73. (a) अनु. 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता।

75. (c) नगरपालिका चुनावों में किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी हेतु उसकी उम्र का 21 वर्ष होना आवश्यक है।

78. (c) 1. एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है (अनुच्छेद 153)

2. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं (अनुच्छेद 217)

3. किसी संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। परंतु राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उपबंध नहीं है।

83. (a) उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवा निवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्रातिधकारी के समक्ष अभिवचन कर सकता है। अनु. 217 (b) एवं अनु. 220

85. (d) भारत में 24 उच्चन्यायालय हैं।

87. (a) संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं कर सकता। साथ ही वही व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है जिसने भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया है।

88. (d) न ही 1 न ही 2

89. (d) 1, 2 और 3

90. (b) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन

93. (b) अनु. 143– उच्चतम न्यायालय की राय जानने संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति। (a) अनु. 142– उच्चतम न्यायालय की आज्ञाप्तियों व आदेशों का प्रवर्तन (c) अनु. 144– विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निबटारे के बारे में विशेष उपबंध (d) अनु. 145– न्यायालय के नियम

94. (d) अनु. 215– उच्च न्यायालय, अनु. 275– अनुदान आदि। अनु. 325– सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार

95. (b) अनु. 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है और सलाह मांगे जाने पर ही न्यायालय अपना मत प्रकट करेगा। इस संदर्भ में न्यायालय के पास स्वयं पहल करने की कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी विषय/मुद्दे पर परामर्श के लिए कह सकता है।

96. (a) संसद प्रशासन पर विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण कायम करती है। ऐसी कुछ प्रमुख समितियां हैं—लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वर्ष 1993 में 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया।

97. (d) (1) भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। (2) गुवाहाटी, कोलकत्ता, मुम्बई, पंजाब, हरियाणा और मद्रास उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एक से अधिक राज्यों पर है। (3) दिल्ली, जो एक केन्द्रशासित प्रदेश है, का अपना उच्च न्यायालय है। (4) अनु. 217 के तहत उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है।

99. (a) यह 2004 में पारित हुआ।

100. (c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद के न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है।